

फेम-2 सब्सिडी में कटौती का असर कम करने की कवायद, कंपनियों पर वाहनों के दाम बढ़ाने का दबाव छोटी बैटरी से दोपहिया सस्ता करने की तैयारी

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जून में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कंपनियों को मिलने वाली फेम-2 योजना (फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) वाली सब्सिडी कम कर दी। इसके तहत सब्सिडी 15,000 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति घंटा से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति घंटा कर दी गई है।

नतीजा कंपनियों पर वाहनों का दाम बढ़ाने को दबाव बढ़ा है। ये दोपहिया पहले से ही काफी महंगे हैं। फिलहाल वाहन कंपनियां इनका दाम और बढ़ाने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहतीं। अब इन कंपनियों ने वाहन में लगने वाली बैटरी की लागत कम करने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके सामने एक विकल्प बैटरी को छोटा करना भी है। किसी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की लागत में तकरीबन

15 हजार रुपये से घटकर सब्सिडी 10 हजार प्रति किलोवॉट प्रति घंटा हुई

दोपहिया के दाम में बैटरी की कीमत का बड़ा हिस्सा



बेचा जा रहा है। अलबत्ता ईवी दोपहिया वाहन विनिर्माताओं ने अपना पोर्टफोलियो फिर से व्यवस्थित करने की तैयारी कर ली है।

40 से 50 फीसदी लागत दोपहिया की बैटरी की होती है आमतौर पर

वर्तमान में दोपहिया बैटरी पैक के दाम 18,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये (एक किलोवॉट से 10 किलोवॉट के बीच) तक होते हैं। यह उसके आकार और उस राज्य पर निर्भर करता है, जिसमें इसे बेचा जा रहा है।

पुर्जे बदलना महंगा पड़ेगा

जानकारों का कहना है कि अगर किसी कंपनी को अन्य पुर्जों में बदलाव करके वाहन की लागत घटानी है, तो यह एक नया मॉडल तैयार करने जैसा होगा। एक सूत्र ने कहा कि लगभग हर कंपनी बैटरी का आकार कम करने के लिए काम कर रही है। इसे तीन किलोवॉट प्रतिघंटा से घटाकर ढाई से दो किलोवॉट प्रति घंटा के दायरे में किया जा रहा है। चार किलोवॉट प्रति घंटे की क्षमता पर वाहन एक बार चार्ज करने पर लगभग 110 से 120 किमी तक चलता है।

पटरी पर लौटी बिक्री

जुलाई के पहले पखवाड़े में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की औसत दैनिक बिक्री पिछले महीने की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत बढ़ चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल वाहन के आंकड़ों के अनुसार जुलाई के पहले 17 दिनों में ई-दोपहिया वाहनों की औसत दैनिक बिक्री जून में बेचे गए 852 वाहनों की तुलना में बढ़कर 1,702 वाहन हो गई है। इस दौरान कुल 28,937 होपहिया बिके जबकि जून में 14,499 वाहन बिके थे।

40 से 50 प्रतिशत हिस्सा बैटरी का रहता है और कंपनियों के सामने फौरी विकल्प बैटरी पैक का आकार कम करना है। बैटरी के आकार में कमी से दाम में कम से कम 20 से 25 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

वारंटी के दौरान पुर्जे बदलने या मरम्मत पर जीएसटी नहीं वसूला जाएगा

मुंबई। वारंटी अवधि के दौरान वस्तुओं की बदली, पुर्जे बदलने या उनकी मरम्मत सेवाओं पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर

चर्चा हुई थी और कंपनियों से जीएसटी न वसूलने को कहा गया है।

गौरतलब है कि कंपनियों द्वारा बेची गई वस्तुओं के खराब होने या टूटने पर उन्हें एक निश्चित अवधि के दौरान

निशुल्क ठीक करना या बदलना पड़ता है। इसे वारंटी या गारंटी अवधि कहा जाता है। इस अवधि में मरम्मत सेवाओं के लिए कुछ कंपनियां जीएसटी वसूलती हैं।